

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -1411/2011/हनुमानगढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,  
श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सिंग्ला राईस एण्ड जनरल मिल्स, हनुमानगढ़ ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.एम.पेडीवाल,  
अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :15.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर, (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स), बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 350/आर.वैट/हनुमानगढ़/2009-10 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61 व 75 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 (दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 25.08.2008) के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.02.2009 के जरिये रिवर्स किये गये टैक्स के संबंध में कायम की गयी मांग राशि ₹1,35,135/- व अधिनियम की धारा 61(2) के तहत आरोपित "रिवर्स टैक्स" की दोगुना शास्ति ₹2,70,770/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26.08.2008 करने पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा औद्योगिक ईकाई स्थापित की जाकर, ईकाई में "धान" का विनिर्माण किया जाता है एवम् उक्त पदार्थों का विक्रय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य व अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने सर्वेक्षण के दौरान जांच कर यह भी पाया कि विनिर्माण प्रक्रिया में "छिलका" जो कर मुक्त है भी प्राप्त होता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पादित माल धान कर योग्य है परन्तु छिलका कर मुक्त उत्पाद है फिर भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत कच्चे माल पर भुगतान किये गये सम्पूर्ण कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में बहीयात व प्रस्तुत विवरणियों में लिया गया है। अतः

लगातार.....2

ऐसी स्थिति में, छिलका कर मुक्त उत्पाद होने के कारण, क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधानों के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अविधिक तरीके से क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने तथा जानबूझकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर करापवंचन करने के कारण, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कर मुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल नरमा कपास पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के अधीन ही अनुज्ञेय है एवम् इस संबंध में क्रय पर भुगतान किये गये कर का अनुपातिक लाभ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में देय है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर योग्य वस्तुओं के विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित कर शेष छिलके पर अनुपातिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार कर, इस संबंध में “रिवर्स-टैक्स” की मांग राशियां कायम कर, अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स लि., श्रीगंगानगर 23 टैक्स अपडेट 360 के प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में, स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(g) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य कच्चे माल के क्रय पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर एवम् इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व पर देय है। कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के मद्देनजर उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18 (1)(g) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से विनिर्मित, कर मुक्त माल "चौकर" की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होना अवधारित कर, "रिवर्स- टैक्स" की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल बिनौला की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अग्रिम तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संचेतन मस्तिष्क से विधिक प्रावधानों के विपरीत, गलत रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लिया गया है, अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानानुसार शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अन्ततः, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में विभागीय अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल कय किया गया था तथा इसे धान के विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें छिलका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक सह-उत्पाद है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त क्रीत कच्चे माल के कुल क्रीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है।



अपील संख्या -1411/2011/हनुमानगढ़

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इस संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 344/2012/भरतपुर निर्णय दिनांक 02.09.2013 को प्रोद्धरित किया गया। अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति आरोपण के संबंध में तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में घोषित की गयी है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं इस सम्बन्ध में कर देयता के अपवंचन के लिये जानबूझकर कोई मिथ्या विवरणी अथवा विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 61(2) के तहत रिवर्स किये गये कर राशि की दोगुना शास्ति आरोपित किये जाने में भी विधिक भूल की गयी है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। पुनः इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 को प्रोद्धरित कर, कथन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानअध्ययन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधनों का गहन अध्ययन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में छिलका कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में क्लेम किये गये समस्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:-.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes

अपील संख्या -1411/2011/हनुमानगढ़

specified in this sub-section.” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है। इस प्रकार माननीय

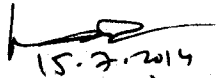


राजस्थान उच्च न्यायालय व खण्डपीठ के प्रोद्धारित निर्णयों में प्रतिपादित विधि से हस्तगत विवादित प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा “रिवर्स-टैक्स” की मांग राशि को अपास्त करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश अभिखण्डित कर, अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी “रिवर्स-टैक्स” की कायम की गयी मांग राशि रु0 1,35,135/- को <sup>प्रथम धारा</sup> पुनर्स्थापित (restore) किया जाता है। जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 344/2012/भरतपुर निर्णय दिनांक 02.09.2013 का प्रश्न है, उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट से संबंधित होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है ।

8. जहां तक अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61(2) के तहत रिवर्स कर की दोगुना शास्ति आरोपण का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धारित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 में उक्त के आरोपण को अविधिक होना अवधारित किया गया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है, अतः उक्त बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. परिणामतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया ।

  
15.7.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य